

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-...../...../2026.

****** अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

द्वारा :-

****** मंत्रिपरिषद्।

विषय :-

सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में रुपये 1,26,07,00,000/- (रुपये एक अरब छब्बीस करोड़ सात लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्पेड, पटना द्वारा कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, सुपौल के अन्तर्गत सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिलों में डेयरी विकास हेतु दही प्लांट, प्रीमियम आईसक्रीम प्लांट, टोटल मिक्स्ट राशन (TMR) प्लांट, भैंस हीफर फार्म, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, नवीन दुग्ध सहकारी समितियों (DCS) के गठन, मिल्क चिलिंग प्लांट एवं BMCU हेतु इंस्टैंट मिल्क चिलिंग सिस्टम की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में रुपये 1,26,07,00,000/- (रुपये एक अरब छब्बीस करोड़ सात लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्पेड, पटना द्वारा कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, सुपौल के अन्तर्गत सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिलों में डेयरी विकास हेतु दही प्लांट, प्रीमियम आईसक्रीम प्लांट, टोटल मिक्स्ट राशन (TMR) प्लांट, भैंस हीफर फार्म, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, नवीन दुग्ध सहकारी समितियों (DCS) के गठन, मिल्क चिलिंग प्लांट एवं BMCU हेतु इंस्टैंट मिल्क चिलिंग सिस्टम की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक-1, 2 एवं 3 के रूप में संलग्न है।

- कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, सुपौल (कोसी मिल्क यूनियन) द्वारा सुपौल, सहरसा एवं मधेपुरा जिलों में दुग्ध उत्पादकों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ते हुए दुग्ध उपार्जन, प्रसंस्करण एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है। संघ के अंतर्गत इन जिलों में कुल 1678 दुग्ध सहकारी समितियाँ (DCS) कार्यरत हैं तथा वर्ष 2025-26 में औसत दुग्ध उपार्जन लगभग 105.39 TLPD दर्ज किया गया

है। विगत वर्षों में संघ के दुग्ध उपार्जन, कारोबार तथा मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पादों की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है।

3. संघ द्वारा वर्तमान में दूध, दही, लस्सी, मट्ठा, प्लेवर्ड मिल्क, पनीर एवं विभिन्न प्रकार की मिठाइयों सहित अनेक मूल्यवर्धित दुग्ध उत्पादों का उत्पादन एवं विपणन किया जा रहा है। विशेष रूप से दही की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा जुलाई 2025 से विभिन्न मिठाइयों का इन-हाउस उत्पादन प्रारंभ किए जाने से संघ के उत्पादों की विविधता एवं बाजार क्षमता में और वृद्धि हुई है। बढ़ती उपभोक्ता मांग, त्योहार एवं ग्रीष्मकालीन मांग तथा कोसी क्षेत्र के साथ-साथ समीपवर्ती बाजारों में सुधा उत्पादों की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए वर्तमान प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग क्षमता का विस्तार आवश्यक हो गया है।
4. दुग्ध उपार्जन में निरंतर वृद्धि के साथ-साथ दूध एवं दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण, शीतलीकरण, मूल्यवर्धन, भंडारण एवं विपणन हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचना का विकास आवश्यक है। वर्तमान क्षमता के सीमित होने के कारण बढ़ती मांग की पूर्ण पूर्ति तथा उपलब्ध दूध के समुचित मूल्यवर्धन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को समय पर एवं बेहतर बाजार उपलब्ध कराने, दुग्ध की गुणवत्ता बनाए रखने तथा दुग्ध सहकारी समितियों के नेटवर्क को और सुदृढ़ करने की भी आवश्यकता है।
5. इसी क्रम में कोसी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन एवं उपार्जन को बढ़ावा देने, उपलब्ध दूध का अधिकतम मूल्यवर्धन करने, आधुनिक प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग क्षमता विकसित करने, शीत श्रृंखला को सुदृढ़ करने तथा पशुपालकों के लिए आवश्यक सहायक सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से दही प्लांट, प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट, TMR मिक्सिंग प्लांट, आवश्यक मशीनरी/प्रसंस्करण सुविधाएँ, नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन, मिल्क चिलिंग/संग्रहण सुविधाएँ तथा BMCU/प्राथमिक दुग्ध शीतलीकरण अवसंरचना सहित कुल 8 परस्पर संबद्ध परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं।
6. ये परियोजनाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं तथा इनके क्रियान्वयन से दुग्ध उपार्जन से लेकर प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, शीतलीकरण, पैकेजिंग एवं विपणन तक की संपूर्ण दुग्ध मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ किया जा सकेगा। इससे न केवल सुधा ब्रांड के उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी, बल्कि दुग्ध उत्पादकों को स्थायी एवं बेहतर बाजार उपलब्ध होगा तथा संघ की वित्तीय स्थिति एवं लाभप्रदता में भी वृद्धि होगी।
7. कोसी क्षेत्र में दुग्ध सहकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, दुग्ध उत्पादकों की आय एवं दुग्ध उपार्जन में वृद्धि करने तथा आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन क्षमता विकसित करने का उद्देश्य है।

8. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोसी, मिथिला और उसके आसपास के सहरसा, मधेपुरा व सुपौल जिलों में 'सुधा ब्रांड' के दही की लगातार बढ़ती बाजार मांग को पूरा करना और स्थानीय डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। पिछले छः वर्षों में यहाँ दही की बिक्री में 11 गुणा से अधिक की वृद्धि हुई है (वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1.42 MTPD से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15.81 MTPD)। दही प्लांट की स्थापना से क्षेत्र में संग्रहित दुग्ध के मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलेगा तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं मानकीकृत सुधा दही उपलब्ध कराया जा सकेगा।
9. कोसी मिल्क यूनियन, सुपौल के नए परिसर (न्यू कैंपस) में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक आधुनिक दही प्लांट स्थापित किया जाना है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इस बड़े प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित प्राक्कलित लागत रुपये 28.00 करोड़ निर्धारित की गई है, जिसमें से लगभग रुपये 8.50 करोड़ सिविल निर्माण और रुपये 19.50 करोड़ अत्याधुनिक मशीनों पर खर्च होंगे।
10. यह प्रोजेक्ट बिहार सरकार की राज्य योजना (State Scheme) के तहत 100% सहायता अनुदान (Grant-in-Aid) द्वारा वित्तपोषित है, जिसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (COMFED) द्वारा किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 18 महीने की समय-सीमा (Timeline) निर्धारित की गई है, जिसके भीतर निविदा, सिविल वर्क, मशीनों की स्थापना और टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। तकनीकी रूप से इस प्लांट में मिल्क स्टैंडराइजेशन, पाश्चुरीकरण, कल्चर इनोक्यूलेशन, ऑटोमैटिक कप फिलिंग और सीलिंग जैसी अत्याधुनिक ऑटोमैटिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही दही को सही तरीके से जमाने और सुरक्षित रखने के लिए तापमान नियंत्रित इनक्यूबेशन रूम, रैपिड चिलर और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी। इस पूरी हाइजीनिक और आधुनिक व्यवस्था से उपभोक्ताओं को शुद्ध और मानकीकृत 'सुधा दही' मिल सकेगा, वहीं कोसी क्षेत्र के हजारों ग्रामीण किसानों से दूध की खरीद बढ़ेगी, जिससे उन्हें समय पर लाभकारी मूल्य मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
11. प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट की स्थापना :-
 - (i) प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कोसी, मिथिला और उसके आसपास के सहरसा, मधेपुरा व सुपौल जिलों में 'सुधा ब्रांड' के आइसक्रीम उत्पादों की लगातार बढ़ती बाजार मांग (विशेषकर अप्रैल से अक्टूबर के सीजन में) को पूरा करना और स्थानीय डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। इस संयंत्र की स्थापना से सुधा ब्रांड के आइसक्रीम उत्पादों की कोसी प्रमंडल एवं समीपवर्ती बाजारों में उपलब्धता एवं पहुँच सुदृढ़ होगी तथा उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा।

- (ii) कोसी मिल्क यूनियन, सुपौल के नए परिसर (न्यू कैंपस) में 10 KLPD क्षमता का एक आधुनिक प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट स्थापित किया जाना है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित प्राक्कलित लागत रुपये 32.00 करोड़ निर्धारित की गई है, जिसमें से रुपये 9.00 करोड़ सिविल निर्माण और रुपये 23.00 करोड़ अत्याधुनिक मशीनों पर खर्च होंगे।
- (iii) यह प्रोजेक्ट बिहार सरकार की राज्य योजना 2026-27 और 2027-28 के तहत 100% सहायता अनुदान (Grant-in-Aid) द्वारा वित्तपोषित है, जिसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (COMFED) द्वारा किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 18 महीने की समय-सीमा (Timeline) निर्धारित की गई है, जिसके भीतर निविदा, सिविल वर्क, मशीनों की स्थापना और टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा।
- (iv) प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट में मिल्क फ़ैट, शुगर और स्टेबलाइजर्स से मिक्स तैयार करने, पाश्चुरीकरण, होमोजिनाइजेशन, एजिंग वैट्स और कंटीन्यूअस फ्रीजर जैसी अत्याधुनिक ऑटोमैटिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही आइसक्रीम को सही आकार देने और सुरक्षित रखने के लिए कप/कोन/स्टिक पैकिंग हेतु ऑटोमैटिक फिलिंग लाइन्स, ब्लास्ट हार्डनिंग टनल और कोल्ड स्टोरेज (-25°C) की व्यवस्था होगी। इस पूरी हाइजीनिक और आधुनिक व्यवस्था से उपभोक्ताओं को प्रीमियम क्वालिटी की आइसक्रीम मिल सकेगी, वहीं कोसी क्षेत्र के 60,283 सहकारी समिति सदस्यों/ग्रामीण किसानों से दूध व फ़ैट की खरीद बढ़ेगी, जिससे उन्हें समय पर लाभकारी मूल्य मिलेगा और क्षेत्र में नए रोजगार पैदा होंगे।

12. टोटल मिक्स्ड राशन (TMR) प्लांट की स्थापना :-

- (i) टोटल मिक्स्ड राशन (TMR) प्लांट नेटवर्क को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य बाढ़ प्रभावित कोसी क्षेत्र में चारे की भारी कमी की समस्या को दूर करना और पशुओं के लिए संतुलित व वैज्ञानिक रूप से तैयार पोषण उपलब्ध कराना है। इन संयंत्रों की स्थापना से दुग्ध उत्पादकों को संतुलित एवं गुणवत्तापूर्ण पशु आहार सुलभ मूल्य पर उपलब्ध होगा, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- (ii) कोसी मिल्क यूनियन के अंतर्गत सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिलों में 2.5 MTPH (मीट्रिक टन प्रति घंटा) क्षमता की कुल 04 टोटल मिक्स्ड राशन (TMR) प्लांट इकाइयाँ स्थापित की जानी हैं। इस परियोजना की कुल अनुमानित प्राक्कलित लागत रुपये 15.32 करोड़ निर्धारित की गई है, जिसमें से रुपये 6.30 करोड़ सिविल वर्क्स (शेड, साइलो और वेब्रिज) और रुपये 9.02 करोड़ अत्याधुनिक प्लांट व मशीनरी पर खर्च होंगे।

- (iii) यह परियोजना बिहार सरकार की राज्य योजना 2026-27 और 2027-28 के तहत 100% सहायता अनुदान (Grant-in-Aid) द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है, जिसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (COMFED) द्वारा किया जाएगा। इस पूरी परियोजना को धरातल पर उतारने और व्यावसायिक रूप से शुरू करने के लिए 12 महीने की समय-सीमा (Timeline) तय की गई है, जिसके तहत चारों चुनिंदा स्थानों पर जमीन आवंटन, सिविल निर्माण और मशीनरी का काम समानांतर रूप से पूरा किया जाएगा।
- (iv) टोटल मिक्स्ड राशन (TMR) प्लांट में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मोटे चारे (जैसे मक्का/धान का पुआल और हरा चारा) के साथ कंसंट्रेट मिक्स (मक्का, खली, चोकर, शीरा, खनिज और विटामिन) को एक निश्चित वैज्ञानिक अनुपात में मिलाकर पौष्टिक टीएमआर (TMR) पशु आहार तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्लांट में रॉ मटेरियल स्टोरेज साइलो, चाफ कटर, कंसंट्रेट मिक्सर, टीएमआर मिक्सर, ऑटोमैटिक बैगिंग-वेइंग सिस्टम और एक आधुनिक क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की जाएगी। विकेंद्रीकृत स्तर पर स्थापित होने वाले टोटल मिक्स्ड राशन (TMR) प्लांट पशुपालक किसानों के लिए परिवहन लागत और समय को कम करेंगे, जिससे बिना पशुओं की संख्या बढ़ाए उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और निजी व असुरक्षित चारा सप्लायर्स पर उनकी निर्भरता खत्म होगी।
13. भैंस हीफर फार्म की स्थापना :-
- (i) भैंस हीफर फार्म की स्थापना फार्म को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कोसी क्षेत्र में खुले बाजारों या असुरक्षित स्रोतों पर किसानों की निर्भरता को खत्म करना और उन्हें उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाली (High-Genetic-Merit) बीमारी-मुक्त मुर्दा नस्ल की गर्भाधान युक्त बछिया (In-calf Heifers) उपलब्ध कराना है। इस फार्म की स्थापना से क्षेत्र में उन्नत नस्ल की भैंसों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे दुग्ध उत्पादक पशुधन की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार होगा तथा दुग्ध उत्पादकों को उन्नत नस्ल की भैंसों रियायती दर पर उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
- (ii) कोसी मिल्क यूनियन, सुपौल के नए परिसर (न्यू कैंपस) में 100 भैंस क्षमता का एक आधुनिक भैंस हीफर फार्म (Buffalo Heifer Farm) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा भूमि आवंटित की जा रही है। इस परियोजना की कुल अनुमानित प्राक्कलित लागत रुपये 18.00 करोड़ निर्धारित की गई है, जिसमें से रुपये 10.50 करोड़ सिविल निर्माण और रुपये 7.50 करोड़ बुनियादी लाइवस्टॉक (पशुधन) व अत्याधुनिक मशीनरी पर खर्च होंगे।
- (iii) यह परियोजना बिहार सरकार की राज्य योजना 2026-27 और 2027-28 के तहत 100% सहायता अनुदान (Grant-in-Aid) द्वारा पूरी तरह से

वित्तपोषित है, जिसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (COMFED) द्वारा किया जाएगा।

- (iv) भैंस हीफर फार्म की स्थापना फार्म पूरे प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए 18 महीने की समय-सीमा (Timeline) निर्धारित की गई है, जिसके भीतर भूमि आवंटन, सिविल निर्माण और पशुधन की खरीद का काम पूरा कर लिया जाएगा, जबकि प्लांट अपने चौथे वर्ष (48वें महीने) से पूरी तरह स्थिर संचालन (Steady-State Operations) की स्थिति में आ जाएगा।
- (v) भैंस हीफर फार्म की स्थापना फार्म में वैज्ञानिक प्रबंधन के तहत उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्लों को पाला जाएगा, जो प्रस्तावित 'सेक्स सॉर्टेड सीमेन' सुविधा के साथ मिलकर नस्ल सुधार कार्यक्रम को गति देगा। बुनियादी ढाँचे के रूप में यहाँ पशु आवास शेड (बछिया और गर्भवती पशुओं के लिए), चारा खेती क्षेत्र, टीएमआर फीडिंग सिस्टम, पशु चिकित्सालय, क्वारंटाइन यूनिट, गोबर प्रबंधन (बायोगैस) प्रणाली और पशुओं की पहचान के लिए आरएफआईडी (RFID) डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। स्थिर संचालन की स्थिति में यह फार्म सालाना लगभग 60 उन्नत नस्ल की बछिया/पशुधन की बिक्री करेगा जिससे ₹0 1.0 से ₹0 1.1 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। यह प्रोजेक्ट कोसी क्षेत्र के 60,000 से अधिक किसानों को वहनीय दरों पर उत्कृष्ट पशुधन देकर उनकी दुग्ध उत्पादकता और आय को बढ़ाने में गेम-चेंजर साबित होगा।

14. नवीन दुग्ध सहकारी समितियों (DCS) का गठन :-

- (i) नवीन दुग्ध सहकारी समितियों (DCS) का गठन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कोसी प्रमंडल के उन असंगठित गांवों और टोलों को औपचारिक डेयरी नेटवर्क से जोड़ना है जो वर्तमान में दुग्ध संग्रहण की मुख्य धारा से बाहर हैं, ताकि नए प्रोसेसिंग प्लांट्स (दही, आइसक्रीम आदि) के लिए कच्चे दूध की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। इससे अनाच्छादित क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों को सहकारी संरचना से जोड़ा जा सकेगा, दुग्ध संग्रहण क्षेत्र का विस्तार होगा तथा कोसी मिल्क यूनियन के दुग्ध संग्रहण आधार में वृद्धि होगी।
- (ii) कोसी मिल्क यूनियन के अंतर्गत सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिलों के दूरदराज और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 500 नई दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों (DCS) के गठन की एक बुनियादी परियोजना प्रस्तावित की गई है। इस जमीनी नेटवर्क विस्तार योजना की कुल अनुमानित प्राक्कलित लागत रुपये 5.00 करोड़ निर्धारित की गई है, जिसके तहत प्रति समिति गठन और बुनियादी उपकरणों के लिए रुपये 1.00 लाख का निवेश किया जाएगा।
- (iii) यह परियोजना भी बिहार सरकार की राज्य योजना 2026-27 और 2027-28 के तहत 100% सहायता अनुदान (Grant-in-Aid) द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है, जिसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव

फेडरेशन लिमिटेड (COMFED) के तहत किया जाएगा। इस व्यापक विस्तार कार्य को धरातल पर उतारने के लिए 12 महीने की समय-सीमा (Timeline) निर्धारित की गई है, जिसके तहत पहले चरण में 200 समितियाँ और दूसरे चरण में 300 समितियों की पहचान, पंजीकरण और पूर्ण एकीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा।

- (iv) गठित होने वाली प्रत्येक नई समिति को ग्राम स्तर पर एक पारदर्शी और आधुनिक दुग्ध संग्रहण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक समिति को इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनालाइजर (Fat/SNF टेस्टिंग हेतु), डिजिटल वेइंग स्केल (वजन मशीन), एल्युमिनियम मिल्क कैनस और बुनियादी स्वच्छता उपकरण प्रदान किए जाएंगे, साथ ही रुपये-लिंकड डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को दूध की सटीक कीमत सीधे उनके बैंक खातों में मिल सके। स्थिर परिचालन (तीसरे वर्ष) तक पहुँचने पर ये 500 समितियाँ प्रतिदिन लगभग 75,000 लीटर (75 TLPD) अतिरिक्त दूध का संग्रहण करेंगी, जिससे करीब 40,000 से 50,000 नए ग्रामीण परिवारों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सीधा बाजार मिलेगा, बिचौलियों पर उनकी निर्भरता समाप्त होगी और कोसी क्षेत्र के डेयरी क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

15. मिल्क चिलिंग प्लांट की स्थापना :-

- (i) मिल्क चिलिंग प्लांट की स्थापना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बेरियाही और बीरपुर जैसे दूध-अधिशेष (Milk-Surplus) क्षेत्रों में कच्चे दूध को तुरंत ठंडा करने की सुविधा देना है, ताकि कोसी क्षेत्र की गर्म, आर्द्र और बाढ़ प्रभावित जलवायु में दूध की गुणवत्ता खराब होने या फटने (Spoilage) के नुकसान को रोका जा सके। इन संयंत्रों की स्थापना से संग्रहित दुग्ध का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण शीतलीकरण सुनिश्चित होगा, जिससे परिवहन के दौरान दुग्ध की गुणवत्ता में गिरावट को रोका जा सकेगा तथा डेयरी संयंत्रों को उच्च गुणवत्ता का कच्चा दूध उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- (ii) कोसी मिल्क यूनियन के अंतर्गत सहरसा जिले के बेरियाही और सुपौल जिले के बीरपुर में 50 KLPD (किलो लीटर प्रतिदिन) क्षमता की कुल 02 मिल्क चिलिंग प्लांट (Milk Chilling Plant) इकाइयाँ स्थापित की जानी प्रस्तावित हैं। इस महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की कुल अनुमानित प्राक्कलित लागत ₹0 18.00 करोड़ निर्धारित की गई है, जिसमें से ₹0 7.00 करोड़ दोनों स्थानों पर सिविल निर्माण (जैसे रिसेशन डॉक, चिलिंग हॉल और साइलो फाउंडेशन) तथा ₹0 11.00 करोड़ अत्याधुनिक प्लांट, रेफ्रिजरेशन मशीनरी और इंसुलेटेड टैंकों पर खर्च होंगे।
- (iii) यह परियोजना भी बिहार सरकार की राज्य योजना 2026-27 और 2027-28 के तहत 100% सहायता अनुदान (Grant-in-Aid) द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है, जिसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव

फेडरेशन लिमिटेड (COMFED) द्वारा किया जाएगा। इस पूरी परियोजना को धरातल पर उतारने और व्यावसायिक रूप से शुरू करने के लिए 14 महीने की समय-सीमा (Timeline) निर्धारित की गई है, जिसके भीतर दोनों चयनित स्थलों पर भूमि का चयन, सिविल निर्माण, मशीनरी की स्थापना और ट्रायल रन का काम पूरा कर लिया जाएगा।

- (iv) मिल्क चिलिंग प्लांट की स्थापना से गांवों से आने वाले कच्चे दूध को तौलने और लैब टेस्टिंग (Fat/SNF और मिलावट जांच) के बाद प्लेट हीट एक्सचेंजर (PHE) तकनीक के जरिए तुरंत 4°C से कम तापमान पर ठंडा किया जाएगा। इस ठंडे दूध को 50 KL क्षमता के इंसुलेटेड साइलो में सुरक्षित रखा जाएगा और फिर इंसुलेटेड मिल्क टैंकरों के माध्यम से आगे की प्रोसेसिंग के लिए मुख्य सुधा डेयरी, सुपौल भेजा जाएगा। बाढ़ के समय ग्रिड बिजली प्रभावित होने की स्थिति से निपटने के लिए यहां मजबूत डीजी (DG) बैक-अप पावर की व्यवस्था होगी। स्थिर परिचालन (70% क्षमता उपयोग) पर ये प्लांट सालाना लगभग 2.31 करोड़ लीटर दूध का शीतलीकरण करेंगे, जिससे करीब ₹0 29-30 करोड़ प्रति वर्ष का अतिरिक्त मूल्य स्थानीय किसानों को मिलेगा, दूध संग्रह का दायरा बढ़ेगा और बाढ़ के कठिन दिनों में भी क्षेत्र की डेयरी व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।

16. BMCU हेतु इंस्टेंट मिल्क चिलिंग सिस्टम की स्थापना :-

- (i) BMCU हेतु इंस्टेंट मिल्क चिलिंग सिस्टम की स्थापना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कोसी क्षेत्र के बाढ़-संभावित और सुदूर ग्रामीण क्लस्टर में अंतिम मील (Last-mile) तक त्वरित शीतलन सुविधा का विस्तार करना है, ताकि मानसून और बाढ़ के दिनों में सड़क संपर्क टूटने या परिवहन में देरी होने पर भी दूध को फटने से बचाया जा सके और उसकी शुद्धता बरकरार रखी जा सके। इससे BMC स्तर पर संग्रहित दुग्ध की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता मिलेगी तथा दुग्ध उत्पादकों को समय पर एवं उचित मूल्य का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।
- (ii) कोसी मिल्क यूनियन के अंतर्गत आने वाले सभी थोक दुग्ध शीतलन केंद्रों (BMC) में 05 KL क्षमता की कुल 15 इकाइयाँ इंस्टेंट मिल्क चिलिंग सिस्टम (Instant Milk Chilling System) स्थापित की जानी हैं। इस रणनीतिक और विकेंद्रीकृत बुनियादी ढांचा परियोजना की कुल अनुमानित प्राक्कलित लागत ₹0 2.25 करोड़ निर्धारित की गई है, जिसमें से ₹0 60 लाख सभी 15 साइटों पर प्लेटफॉर्म व फाउंडेशन के सिविल कार्यों पर और ₹0 1.65 करोड़ अत्याधुनिक स्किड-माउंटेड रैपिड चिलिंग मशीनों, पावर बैक-अप व स्वच्छता उपकरणों पर खर्च होंगे।
- (iii) यह परियोजना भी बिहार सरकार की राज्य योजना 2026-27 और 2027-28 के तहत 100% सहायता अनुदान (Grant-in-Aid) द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है, जिसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव

फेडरेशन लिमिटेड (COMFED) के सहयोग से कोसी मिल्क यूनियन द्वारा किया जाएगा। इस पूरी योजना को धरातल पर उतारने के लिए 9 से 10 महीने की समय-सीमा (Timeline) निर्धारित की गई है, जिसके तहत सभी 15 चयनित बीएमसी (BMC) स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से सिविल वर्क, मशीनों की आपूर्ति, स्थापना और रूट इंटीग्रेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा।

- (iv) इन प्रणालियों में गांवों से संग्रहित होकर आने वाले कच्चे दूध को तुरंत 4°C से कम तापमान पर रैपिड-चिल किया जाएगा और उसे 5 KL क्षमता के कॉम्पैक्ट इंसुलेटेड स्टोरेज में सुरक्षित रखा जाएगा। इन कॉम्पैक्ट इकाइयों का डिजाइन स्किड-माउंटेड है, जिससे अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण या बड़े सिविल निर्माण की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है, और इन्हें पहले से चल रहे बाढ़-आश्रय (Flood-shelter) केंद्रों जैसे जादिया, आलमनगर, झलाड़ी और किशनपुर के सफल मॉडल पर प्राथमिकता से स्थापित किया जाएगा। स्थिर संचालन (65% क्षमता उपयोग) पर पहुँचने के बाद ये 15 इकाइयाँ मिलकर सालाना लगभग 1.61 करोड़ लीटर दूध का प्रसंस्करण करेंगी, जिससे रु0 60.00 लाख का वार्षिक परिचालन अधिशेष प्राप्त होगा। यह प्रोजेक्ट कोसी क्षेत्र के हजारों छोटे पशुपालकों को विपरीत मौसम में भी दूध की सुरक्षित बिक्री और पारदर्शी आय की गारंटी देकर ग्रामीण विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगा।

17. सेक्स सॉर्टेड सीमेन की व्यवस्था

- (i) सेक्स सॉर्टेड सीमेन की व्यवस्था को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कृत्रिम गर्भाधान (Conventional AI) की सीमाओं को दूर करना है, जिसमें नर और मादा बछड़ों के जन्म की संभावना बराबर होती है, और इस उन्नत तकनीक के माध्यम से मादा बछियों (Female Calves) के जन्म की दर को 90% से अधिक तक बढ़ाना है। इसके प्रयोग से मादा बछियों के जन्म दर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे दुग्ध उत्पादक पशुधन की संख्या एवं गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा तथा दुग्ध उत्पादकों की दीर्घकालिक आय सुनिश्चित होगी।
- (ii) कोसी मिल्क यूनियन के संपूर्ण कार्यक्षेत्र (सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिलों) के लिए 3 लाख डोज सेक्स सॉर्टेड सीमेन (Sex Sorted Semen) की उपलब्धता सुनिश्चित करने की एक रणनीतिक परियोजना प्रस्तावित की गई है। इस तकनीक-आधारित महत्वपूर्ण परियोजना की कुल अनुमानित प्राक्कलित लागत रु0 7.50 करोड़ निर्धारित की गई है, जिसके तहत रु0 250 प्रति डोज की दर से 3 लाख डोज सीमेन की व्यवस्था की जाएगी।
- (iii) यह परियोजना भी बिहार सरकार की राज्य योजना 2026-27 और 2027-28 के तहत 100% सहायता अनुदान (Grant-in-Aid) द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है, जिसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव

- फेडरेशन लिमिटेड (COMFED) के दिशा-निर्देशों में कोसी मिल्क यूनियन द्वारा किया जाएगा। इस पूरी योजना को लागू करने और वितरित करने के लिए 14 महीने की समय-सीमा (Timeline) निर्धारित की गई है, जिसके भीतर आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ कर सीमेन डोज को जमीनी स्तर तक पहुँचाया जाएगा।
- (iv) यह परियोजना कोसी मिल्क यूनियन के मौजूदा 290 कृत्रिम गर्भाधान (AI) केंद्रों के नेटवर्क को सीधे और विश्वसनीय रूप से सेक्स सॉर्टेड सीमेन की पहुंच प्रदान करेगी, जिससे बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता खत्म होगी और लॉजिस्टिक्स की लागत व समय में बचत होगी। यह तकनीक सीधे तौर पर प्रस्तावित 'भैंस हीफर फार्म' के साथ मिलकर काम करेगी ताकि क्षेत्र में उच्च आनुवंशिक क्षमता (High-Genetic-Merit) वाली दुधारू भैंसों और गायों की संख्या तेजी से बढ़ाई जा सके। शत-प्रतिशत अनुदान पर आधारित होने के कारण यह सीमेन पशुपालक किसानों को अत्यधिक रियायती और किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसान परिवारों पर अनुत्पादक नर बछड़ों के पालन-पोषण का आर्थिक बोझ कम होगा, दुग्ध उत्पादकता में दीर्घकालिक वृद्धि होगी और कोसी क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।
18. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि में होने वाले व्यय का विकलन निम्नलिखित बजट शीर्ष से किया जायेगा :-
- (i) मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102 -डेरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या-02, उप शीर्ष-0119 -आधुनिक तकनीकों से डेयरी का समग्र विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन तंत्र सुदृढ़ीकरण सात निश्चय-3, विपत्र कोड 02-2404001020119, विषय शीर्ष-0119.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से विकलनीय होगा।
- (ii) मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102 -डेरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या-02, उप शीर्ष-0119 -आधुनिक तकनीकों से डेयरी का समग्र विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन तंत्र सुदृढ़ीकरण सात निश्चय-3, विपत्र कोड 02-2404001020119, विषय शीर्ष-0119.31.06 -सहायक अनुदान गैर वेतन मद से विकलनीय होगा।
19. राशि का व्यय संदर्भित विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष में अनुपूरक आगणन से बजट उपबंध प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।
20. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यकारी दिशा-निर्देश विभाग द्वारा समय-समय पर अलग से निर्गत किया जायेगा।
21. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना एवं प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

22. इस योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।
23. इस योजना अंतर्गत कॉम्फेड, पटना को स्वीकृत राशि का भुगतान सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर निदेशक, गव्य द्वारा एकमुस्त कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।
24. कॉम्फेड द्वारा इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों का सम्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर कराया जायेगा।
25. इस योजना को ससमय पूर्ण करने की जवाबदेही कॉम्फेड, पटना की होगी तथा योजनाओं का अनुश्रवण सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार तथा बिहार विकास मिशन द्वारा किया जाएगा।
26. इस योजना का क्रियान्वयन ससमय पूर्ण होने के पश्चात अठारह माह की अवधि के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र (बी०टी०सी० प्रपत्र-42A में) एवं व्यय राशि के अभिलेख सहित कॉम्फेड, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
27. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
28. दिनांक-16.09.2026 को सम्पन्न लोक वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका-6 एस०एस०(6)96/2026 के पृष्ठ 15-14/प०.
29. दिनांक-23.09.2026 को मद संख्या-08 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)96/2026 (पृष्ठ-18/टि०).
30. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)96/2026 के पृष्ठ-19/टि० तथा डायरी सं०-680, दिनांक-28.09.2026.
31. वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(कुमार स्वीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)96/2026-5342 /पटना-15, दिनांक-...०१/...१०/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)96/2026-5342 /पटना-15, दिनांक-...०१/...१०/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)96/2026-5342 /पटना-15, दिनांक-...०१/...१०/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)96/2026-5342 /पटना-15, दिनांक-...०१/...१०/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)96/2026-5342 /पटना-15, दिनांक-...०१/...१०/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-23.09.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-08 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)96/2026-5342 /पटना-15, दिनांक-...०१/...१०/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा-06 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)96/2026-5342 /पटना-15, दिनांक-...०१/...१०/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)96 / 2026-

/पटना-15, दिनांक-..... / / 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-1

सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में रुपये 12607.00 लाख (रुपये एक अरब छब्बीस करोड़ सात लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना द्वारा कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, सुपौल के अन्तर्गत सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिलों में डेयरी विकास हेतु दही प्लांट, प्रीमियम आईस्क्रीम प्लांट, टोटल मिक्स्ड राशन (TMR) प्लांट, भैंस हीफर फार्म, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, नवीन दुग्ध सहकारी समितियों (DCS) के गठन, मिल्क चिलिंग प्लांट एवं BMCU हेतु इंस्टैंट मिल्क चिलिंग सिस्टम की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

विपत्र कोड 02-2404001020119, विषय शीर्ष-0119.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद।

(राशि लाख में)

क्र० सं०	विवरणी	वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना हेतु राशि	वित्तीय वर्ष 2027-28 में योजना हेतु राशि	कुल राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार
1	दही प्लांट	1120.00	1680.00	2800.00	निदेशक (गव्य) या इनके द्वारा प्राधिकृत/नामित पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना
2	प्रीमियम आईस्क्रीम प्लांट	1280.00	1920.00	3200.00		
3	टोटल मिक्स्ड राशन (TMR) प्लांट	612.80	919.20	1532.00		
4	भैंस हीफर फार्म	720.00	1080.00	1800.00		
5	नवीन दुग्ध सहकारी समितियों (DCS) के गठन	200.00	300.00	500.00		
6	मिल्क चिलिंग प्लांट	720.00	1080.00	1800.00		
7	BMCU हेतु इंस्टैंट मिल्क चिलिंग सिस्टम	90.00	135.00	225.00		
कुल योग :-		4742.80	7114.20	11857.00		

5342
01/10/26

सरकार के संयुक्त सचिव



अनुलग्नक -2

सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में रुपये 12607.00 लाख (रुपये एक अरब छब्बीस करोड़ सात लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना द्वारा कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, सुपौल के अन्तर्गत सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिलों में डेयरी विकास हेतु दही प्लांट, प्रीमियम आईस्क्रीम प्लांट, टोटल मिक्स्ट राशन (TMR) प्लांट, भैंस हीफर फार्म, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, नवीन दुग्ध सहकारी समितियों (DCS) के गठन, मिल्क चिलिंग प्लांट एवं BMCU हेतु इंस्टैंट मिल्क चिलिंग सिस्टम की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

विपत्र कोड 02-2404001020119, विषय शीर्ष-0119.31.06 -सहायक अनुदान गैर वेतन मद।

(राशि लाख में)

क्र० सं०	विवरणी	वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना हेतु राशि	वित्तीय वर्ष 2027-28 में योजना हेतु राशि	कुल राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार
1	सेक्स सॉर्टेड सीमेन	300.00	450.00	750.00	निदेशक (गव्य) या इनके द्वारा प्राधिकृत/नामित पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना
कुल योग		300.00	450.00	750.00		

5342
01/10/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-3

सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में रुपये 12607.00 लाख (रुपये एक अरब छब्बीस करोड़ सात लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना द्वारा कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, सुपौल के अन्तर्गत सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिलों में डेयरी विकास हेतु दही प्लांट, प्रीमियम आईस्क्रीम प्लांट, टोटल मिक्स्ड राशन (TMR) प्लांट, भैंस हीफर फार्म, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, नवीन दुग्ध सहकारी समितियों (DCS) के गठन, मिल्क चिलिंग प्लांट एवं BMCU हेतु इंस्टैंट मिल्क चिलिंग सिस्टम की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

(राशि लाख में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना हेतु राशि	वित्तीय वर्ष 2027-28 में योजना हेतु राशि	कुल राशि
1	विपत्र कोड 02-2404001020119, विषय शीर्ष-0119.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद	दही प्लांट	1120.00	1680.00	2800.00
2		प्रीमियम आईस्क्रीम प्लांट	1280.00	1920.00	3200.00
3		टोटल मिक्स्ड राशन (TMR) प्लांट	612.80	919.20	1532.00
4		भैंस हीफर फार्म	720.00	1080.00	1800.00
5		नवीन दुग्ध सहकारी समितियों (DCS) के गठन	200.00	300.00	500.00
6		मिल्क चिलिंग प्लांट	720.00	1080.00	1800.00
7		BMCU हेतु इंस्टैंट मिल्क चिलिंग सिस्टम	90.00	135.00	225.00
8	विपत्र कोड 02-2404001020119, विषय शीर्ष-0119.31.06 -सहायक अनुदान गैर वेतन मद।	सेक्स सॉर्टेड सीमेन	300.00	450.00	750.00
		कुल	5042.80	7564.20	12607.00

5342
01/10/26

(रुपये एक अरब छब्बीस करोड़ सात लाख) मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव